सत्यमेव जयते

भारत सरकार

बजट की

मुख्य

विशेषताएं

2024-2025

जुलाई, 2024

वित्त मंत्रालय

बजट प्रभाग

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

‘विकसित भारत’ के हमारे लक्ष्य का रोडमैप

4 मुख्य जातियों पर ध्यान

बजट का मुख्य विषय

01 रोजगार

02 कौशल प्रशिक्षण

03 एमएसएमई

04 मध्यम वर्ग

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं

कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

01

परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान

उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा

राष्ट्रीय सहकारिता नीति

सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुँमुखी विकास के लिए

आत्मनिर्भरता

सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए

सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला

उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना

नई किस्मों को शुरू करना

किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।

प्राकृतिक कृषि

- अगले 2 वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी।
- 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

झींगा उत्पादन और निर्यात

- झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई)

- 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डीपीआई
- 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण
- जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना

विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं

रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

02

पीएम पैकेज (रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं)

योजना - क
पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले

- सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रु. तक 1 माह का वेतन
- इससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है

योजना - ख
विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

- पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबद्ध
- प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन
- इससे 30 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा।

योजना - ग
नियोक्ताओं को सहायता

- सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी
- इससे 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की आशा

- उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना तथा शिशु गृहों की स्थापना करना

- सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण
- इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है

- घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता
- प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई-वाउचर
- 3% वार्षिक ब्याज सहायता

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा
- परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा
- उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे

पीएम पैकेज (4 योजना)

विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं

समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

03

पूर्वोदय: *विकास भी विरासत भी*

- विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए योजना। इसमें बिहार, झारखंड पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।
- गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर।

महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजनाओं के लिए 3 **लाख** करोड़ रुपए से अधिक आवंटन।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: 63,000 गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार। इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में **इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक** की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम:

- वित्त वर्ष 24-25 में 15,000 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी।
- देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करना।
- विशाखापट्टनम-चैन्नै औद्योगिक कॉरिडोर पर कोपार्थी नोड में और हैदराबाद-बंगलूरू औद्योगिक कॉरिडोर में ओरवाकल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचना

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं

विनिर्माण और सेवाएं

04

- विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना
- एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल
- ट्रेड्स में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा
- मुद्रा ऋण: "तरूण" श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया।
- खाद्य अविकिरणन (इरैडिएशन), गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाईयां
- स्ट्रेस अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता
- राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत बारह औद्योगिक पार्क
- वीजीएफ सहायता के साथ पीपीपी मोड में औद्योगिक कामगारों के लिए डॉर्मेट्री टाइप आवास के साथ किराया आवासन
- घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन
- दिवालियापन समाधान में गति लाने के लिए अधिकरण और अपील अधिकरण को सुदृढ़ करना और अतिरिक्त अधिकरण स्थापित करना।

इंटर्नशिप अवसर

पीएम पैकेज (5वीं योजना)

- 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना
- सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रतिमाह ₹5,000 रुपए का भत्ता और ₹6,000 की एककालिक सहायता।

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं

शहरी विकास

05

स्टाम्प ड्यूटी

महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना

स्ट्रीट मार्केट

चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना की परिकल्पना

ट्रांजिट उन्मुख विकास

30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास

जल प्रबंधन

जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं तथा विश्वनीय परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों को सेवाएं उपलब्ध कराना

आवास संबंधी आवश्यकताएं

पीएम आवास योजना शहरी 2.0

10 लाख करोड़ रु. का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्य वर्ग की आवश्यकताएं पूरी होंगी

अधिक उपलब्धता के साथ कुशल तथा पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए सामर्थ्यकारी नीतियां तथा विनियम लागू किए जाएंगे।

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं

ऊर्जा सुरक्षा

06

नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल

- भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना
- भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास

पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी

बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के सहज एकीकरण के लिए

एयूएससी ताप विद्युत संयंत्र

एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा।

ऊर्जा लेखा-परीक्षा

- सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता
- 60 कलस्टरों में ग्रेड ऊर्जा लेखा-परीक्षा की सुविधा, अगले चरण में इसे 100 कलस्टरों तक बढ़ाया जाएगा।

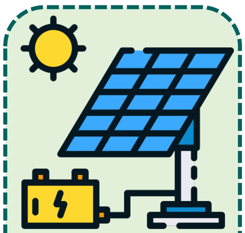

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

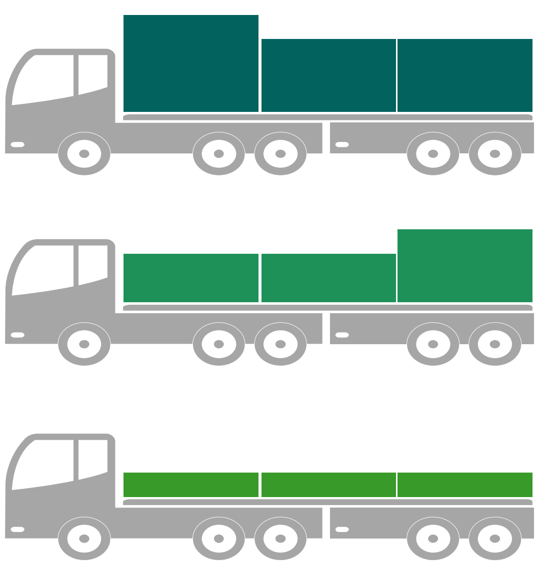

1 करोड़
घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी

300
यूनिट तक प्रतिमाह

अब तक 1.28 करोड़
पंजीकरण और 14 लाख आवेदन

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं

अवसंरचना

07

अवसंरचना के लिए **₹11,11,111** का प्रावधान (जीडीपी का 3.4%).

संसाधन आबंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में **₹1.5** लाख करोड़

25,000 ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए पीएनजीएसवाई का चरण IV शुरू किया जाएगा

सिंचाई एवं बाढ़ उपशमन

- कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए ₹ 11500 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ वित्तीय सहायता
- असम, सिक्किम और उत्तराखण्ड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता
- हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं

अवसंरचना

07

पर्यटन

- काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर **विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर** और **महाबोधि मंदिर कॉरिडोर** का विकास
- हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल **राजगीर** के लिए व्यापक विकास पहल।
- नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा **नालंदा** का एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास।
- **ओडिशा** को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरी, वन्यजीव अभ्यारण्यों, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और मनोरम समुद्र तट के विकास के लिए सहायता।

नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास

08

- मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी।
- 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तपोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र-प्रेरित अनुसंधान और नवप्रवर्तन
- **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था:** 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाना है।

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं

अगली पीढ़ी के सुधार

09

ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्य

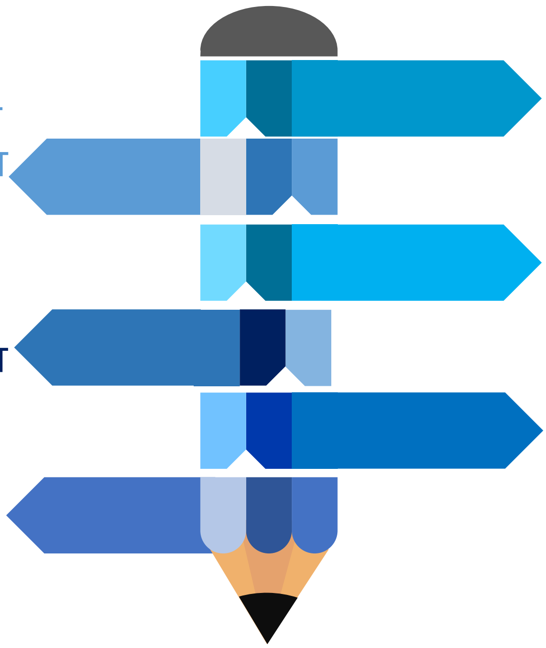

सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू-आधार

शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ भू-अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा

कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण

वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप-प्रभाग का सर्वेक्षण

भू-रजिस्ट्री बनाई जाएगी

किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा

जलवायु वित्तपोषण के लिए टैक्सोनॉमी: जलवायु अनुकूलन और उपशमन से संबंधित निवेशों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी

एफडीआई और ओवरसीज निवेश: एफडीआई को सरल करने और ओवरसीज निवेश के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया सरलीकरण।

एनपीएस वात्सल्य: अवयस्कों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना

डाटा संचालन में सुधार, आंकड़ों और सांख्यिकी का संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रबंधन

नई पेंशन योजना (एनपीएस): संगत समस्याओं का समाधान करने, आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने तथा राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक समाधान निकाला जाएगा।

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

मजबूत आर्थिक आधार

चालू खाता घाटे में सुधार

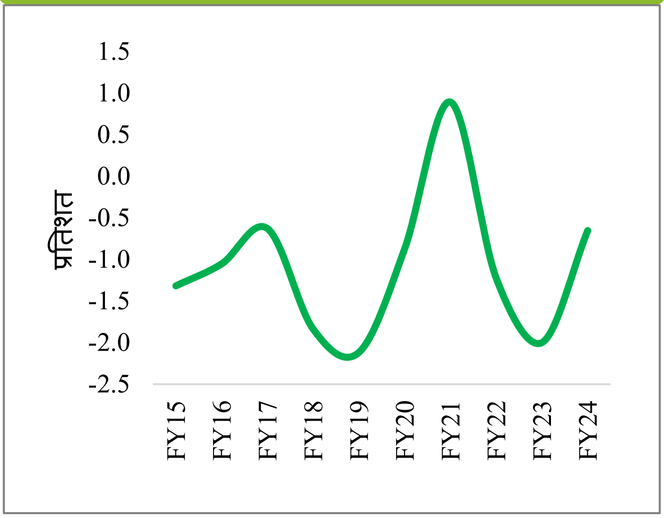

वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 8.2 प्रतिशत रही

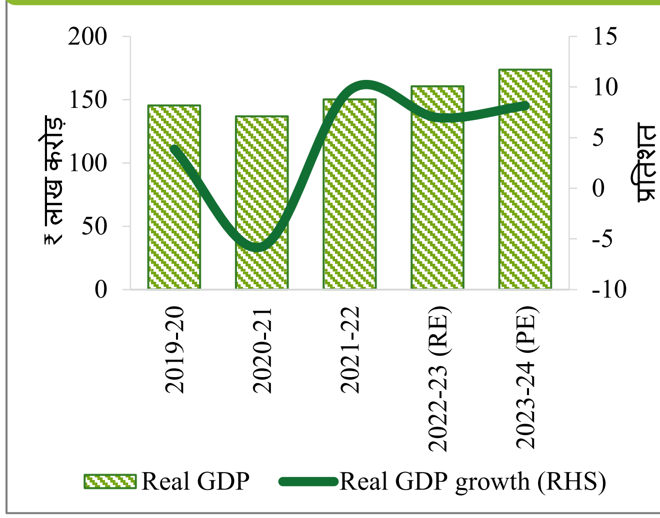

विस्तारणीय पीएमआई इंडेक्स

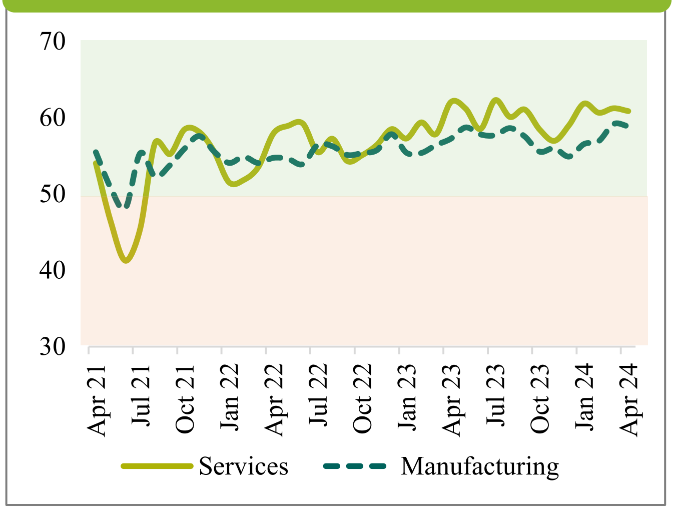

एससीबी के सकल एनपीए में कमी

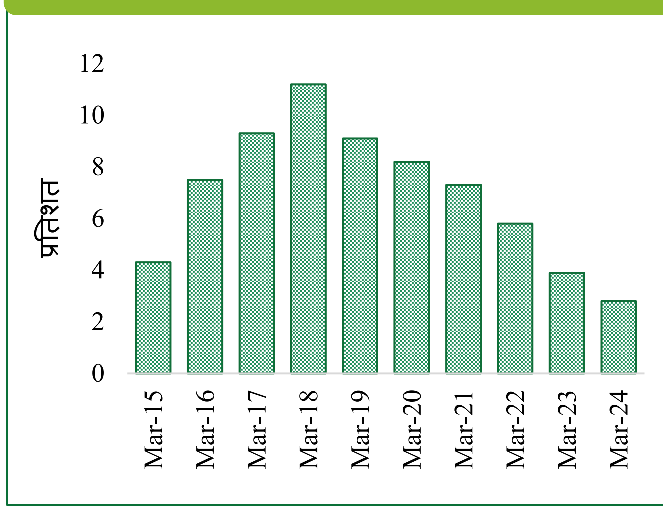

जीडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी

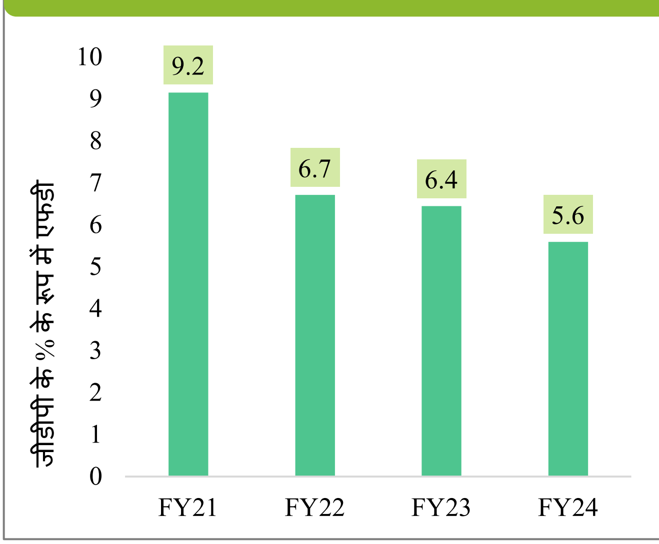

मुद्रास्फीति नियंत्रण

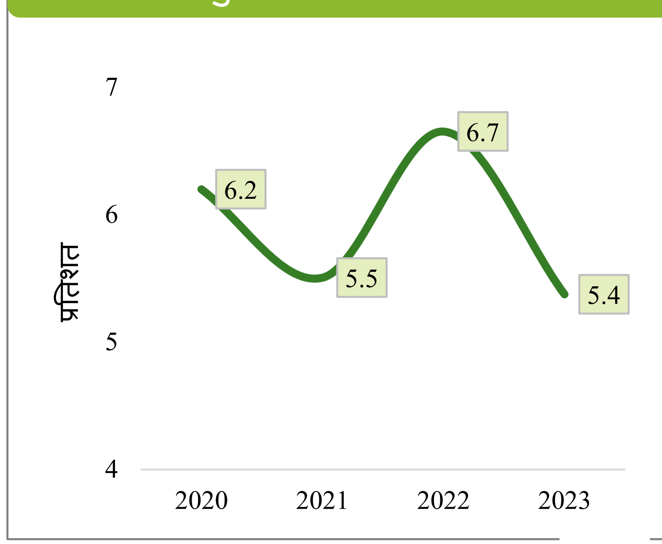

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

कर प्रस्ताव

करों का सरलीकरण

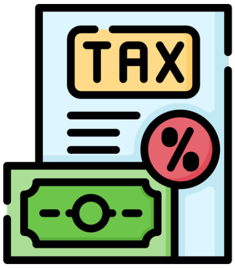

- आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा
- धर्मार्थ संस्थाएं एवं टीडीएस का सरलीकरण
- मुकदमेबाजी और अपील
- कर आधार में वृद्धि करना

क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क के प्रस्ताव

व्यापार में आसानी, शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने और विवादों को कम करने के लिए कर संरचना की व्यापक समीक्षा

सीमा शुल्क में परिवर्तन	लाभ पाने वाले क्षेत्र
कैंसर की 3 और दवाइयों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट	किफायती दवाइयां
मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और चार्जर पर बीसीडी घटाकर 15% करना	मोबाइल उद्योग
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% करना	घरेलू मूल्य संवर्धन
झींगा और फिश फीड पर बीसीडी घटाकर 5% करना	समुद्री निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि
सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट	ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए सहायता
25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट	महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को बढ़ावा

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

अनुपालन का बोझ कम करने के लिए, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना

पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाना

- वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा।
- सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि के लाभों पर **12.5%** कर लगेगा।
- वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रतिवर्ष किया जाएगा।

रोजगार और निवेश

- निवेशकों के सभी वर्गों के लिए **एंजेल कर** समाप्त किया जाएगा।
- **घरेलू क्रूज** चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था।
- विदेशी खनन कंपनियों (अपरिष्कृत हीरे बेचने वाले) के लिए **सेफ हार्बर दरों** का प्रावधान करना।
- विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर की दर 40% से घटाकर **35%** की गई है।

नई कर व्यवस्था को सरल बनाना

₹17,500 तक की बचत

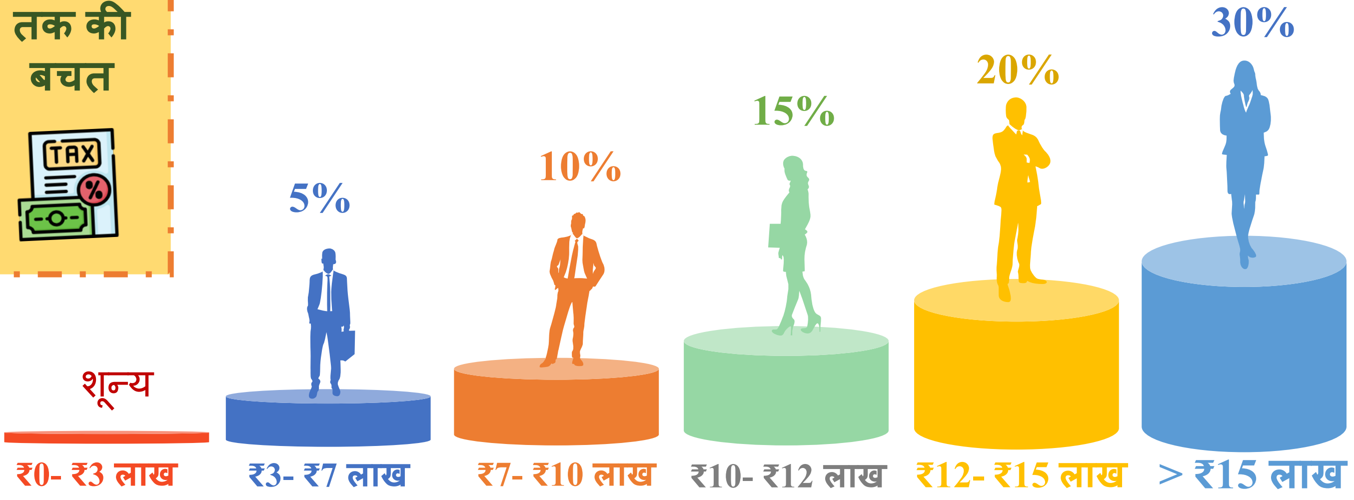

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 की गई है

पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की गई है

रूपया कहां से आता है

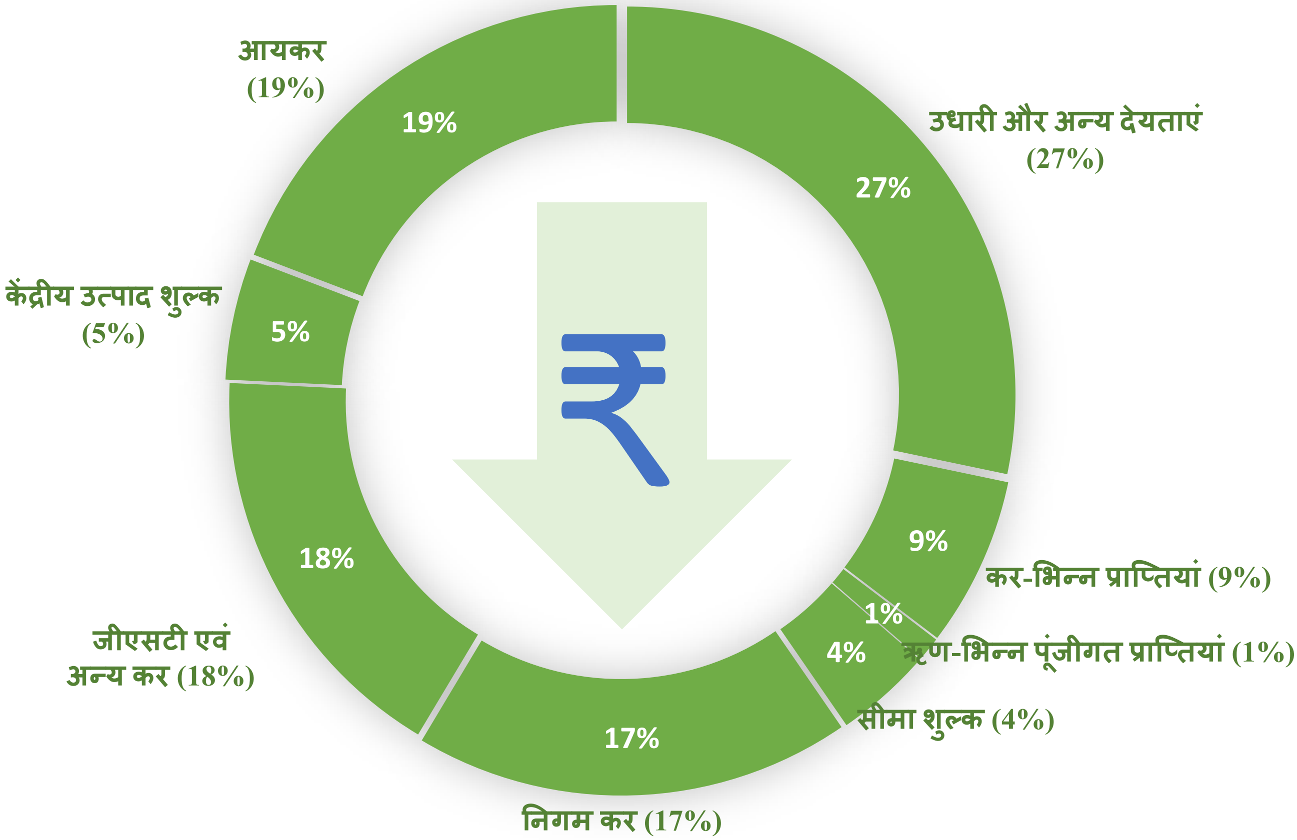

रूपया कहां जाता है

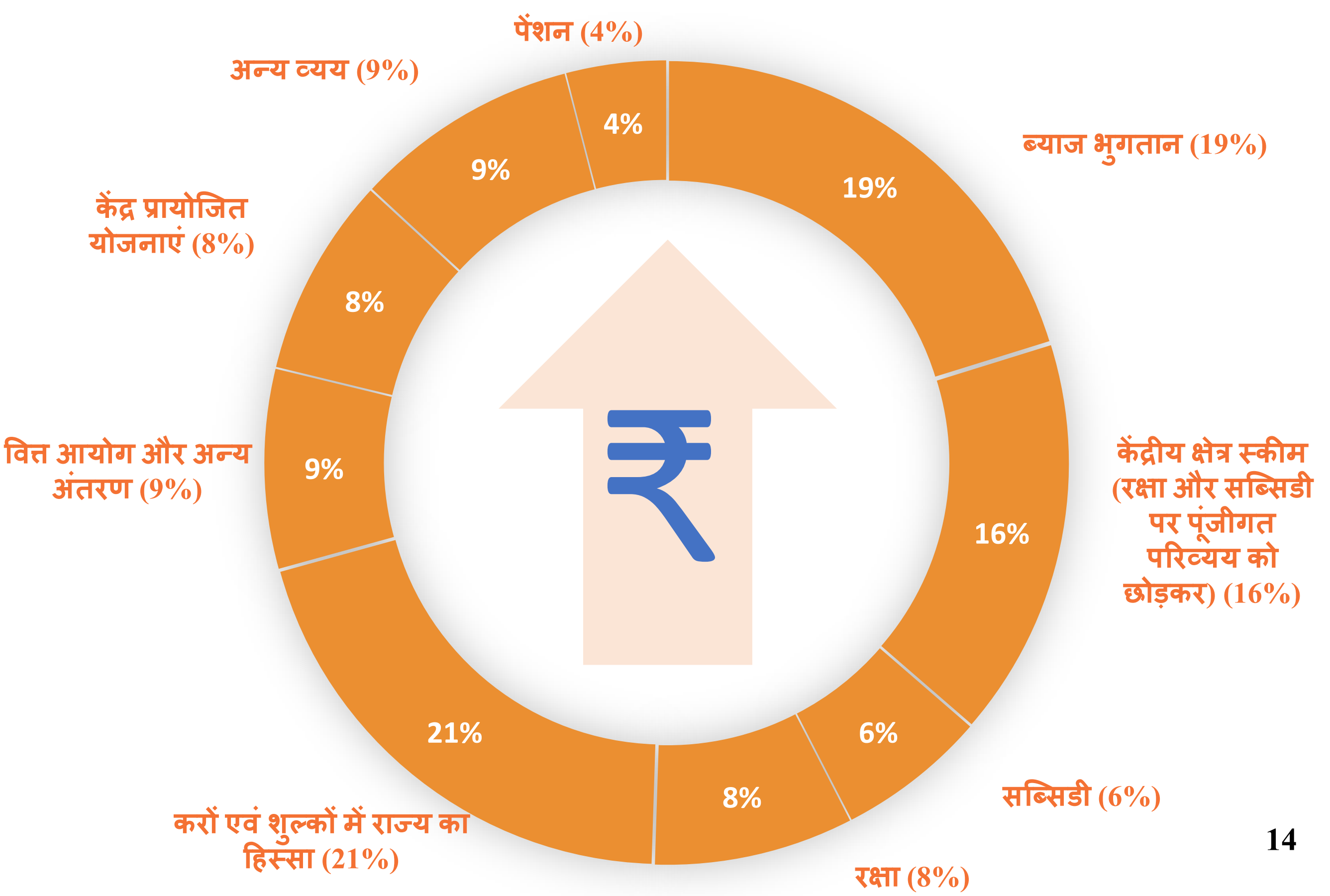

प्रमुख मदों के लिए व्यय

₹ करोड़ में

रक्षा	4,54,773
ग्रामीण विकास	2,65,808
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1,51,851
गृह	1,50,983
शिक्षा	1,25,638
सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार	1,16,342
स्वास्थ्य	89,287
ऊर्जा	68,769
समाज कल्याण	56,501
वाणिज्य और उद्योग	47,559

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

प्रमुख स्कीमों के लिए आबंटन (₹ करोड़ में)

मनरेगा

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
60,000	86,000

अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
840	1,200

नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
442	2,228

औषध उद्योग के लिए पीएलआई

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
1,200	2,143

सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
3,000	6,903

सौर ऊर्जा (ग्रिड)

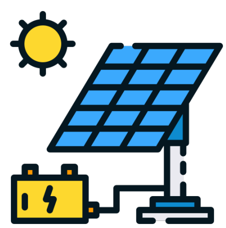

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
4,970	10,000

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-एलपीजी

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
180	1,500

आईडीईए स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन

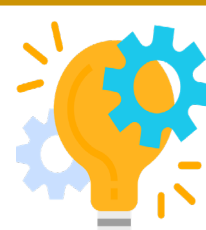

2023-24(ब.अ.)	2024-25(ब.अ.)
1,300	3,849

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"

प्राप्तियां

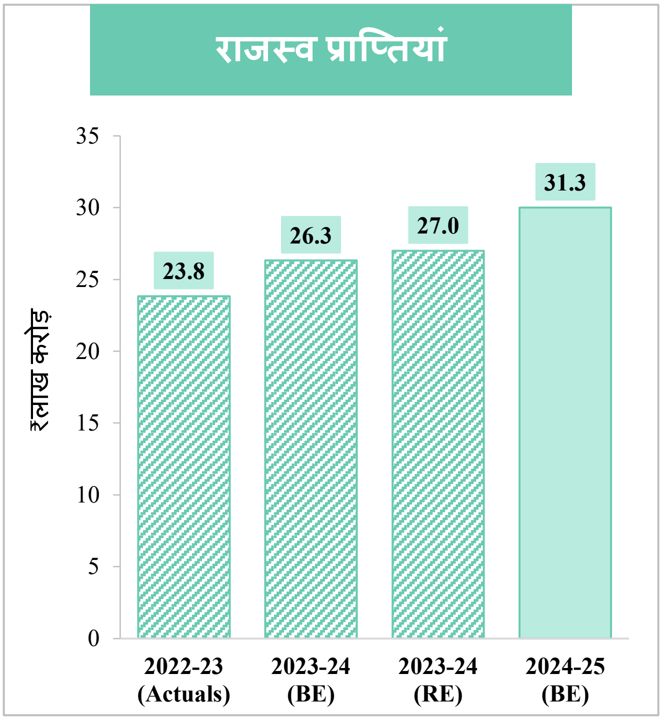

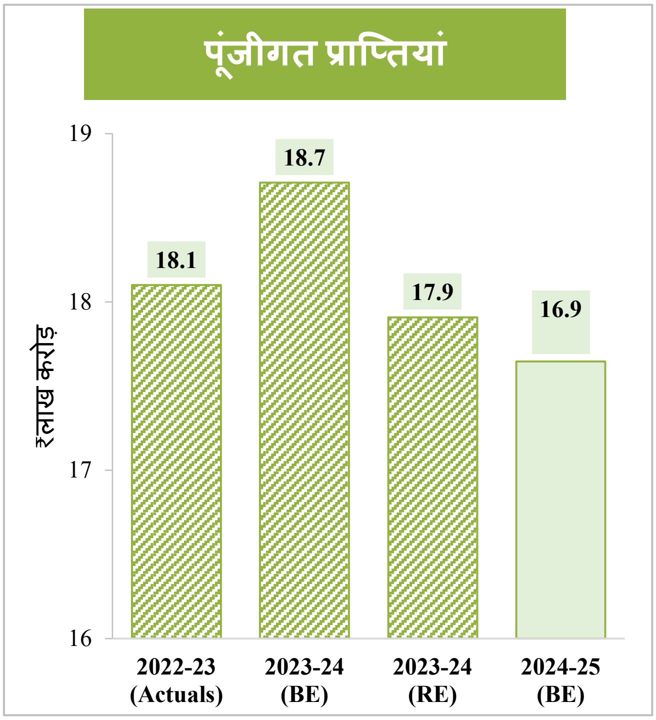

व्यय

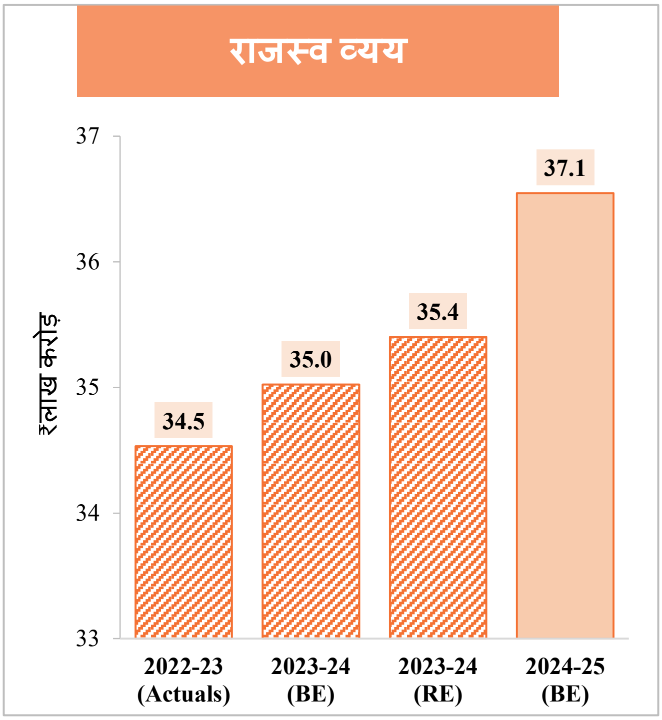

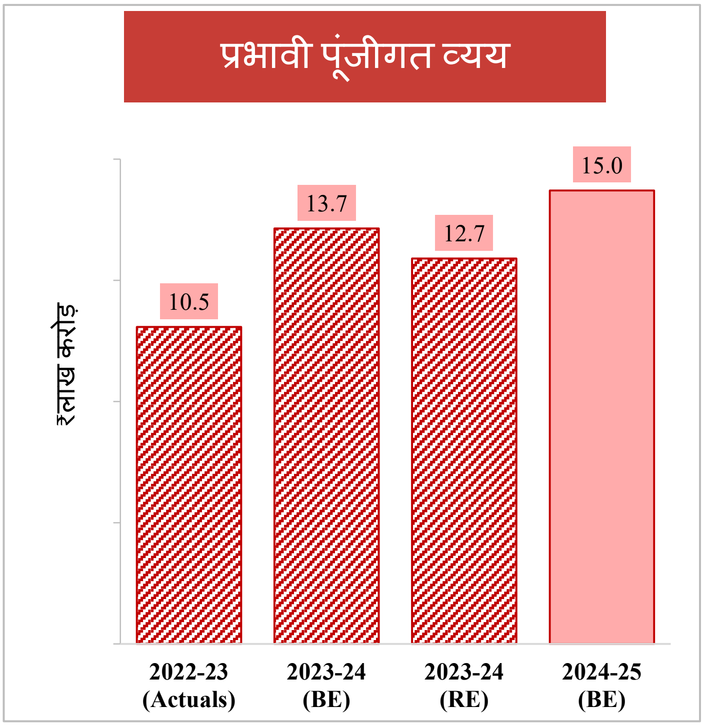

Join Telegram Group "@gkrakeskjangid"